LOK SABHA

Monday, July 31, 1978/Sravana 9, 1900 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. SPEAKER: Q. No. 203...

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, I want to make a submission. There was a ballot for today and I was told that my number was third; I gave the priority also. But my name is not there in the list.

MR. SPEAKER: I will look into the matter.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: This is not the first time. It happens many times. You ask your office to be more particular about it.

MR. SPEAKER: I will look into it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: About Questions, we are becoming more and more disappointed. 15 days have passed and not a single Short Notice Question, has been admitted. The questions which are admitted in the Rajya Sabha are not admitted in the Lok Sabha. The Lok Sabha is becoming a closed-door affair. I am sorry to say that.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Why has it not come in the list? I must be told about it. You direct them. This is not the first time. I send five Questions every day.

MR. SPEAKER: I will look into the matter.

SHRI K. LAKKAPPA: Important Questions, Call Attention notices and Short Notice Questions have not been admitted. Only unimportant Questions are being put on the list. I want you to reconsider all those issues.

MR. SPEAKER: Q. No. 203;—Shri C. N. Visvanathan—not here; Shri P. Thiagarajan—not here. Q. No. 204; Shri Janardhana Poojary—not here; Shri Pradyumna Bal—not here.

Q. No. 205.

पश्चिम बंगाल में साक्षरता

*205. **श्री राज कृष्ण डान :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय पश्चिम बंगाल राज्य का स्थान साक्षरता की दृष्टि से सर्वोच्च था और अब वह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 11 वें स्थान पर आ चुका है ; और

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य में साक्षरता बढ़ाने के लिए वर्तमान केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) No census data are available to show the position of West Bengal

in regard to literacy at the time of Independence. The first Census of independent India was held in 1951. According to this Census, the literacy position of West Bengal (excluding 0—4 age-group) in relation to other States and Union Territories in the country was *fifth*. According to 1961 and 1971 Censuses, the literacy position of the State (excluding 0—4 age-group) was *eleventh* and *twelfth* respectively.

(b) In order to eradicate illiteracy from the country, the major thrust would be on two priority programmes of universalisation of elementary education and National Adult Education Programme. In West Bengal, 43.13 lakh additional un-enrolled children in the age-group 6—14 age planned to be covered during 1978—83 to achieve the goal of Universalisation of elementary education. Under the National Adult Education Programme, it is proposed to cover the entire illiterate population of 72.89 lakhs in the age-group 15—35 in West Bengal by extending adult education facilities to them in a phased manner. The Primary responsibility for implementing the Schemes rests with the State Government. It is hoped that with the implementation of these two programmes, the literacy position would improve substantially.

SHRI RAJ KRISHNA DAWN: The statement which has been laid on the Table of the House by the hon. Minister shows that the literacy position of West Bengal in relation to other States and union territories is hopeless more than what I had asked in the Question. The statement says that according to the 1971 Census, the literacy position of west Bengal was twelfth as against eleventh, as I have stated in my Question. Today, we are in 1978 and we can expect more deterioration in the educational sphere of West Bengal. In view of that, I would like to know from the hon. Minister (a) how many times the Government of West Bengal, if at all, drew the attention of the Government of India to this grave situation in educational sphere.

(b) whether they have asked for more grants to improve the literacy position in the State and what the Government of India did in this matter.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: With regard to supplementary question (1), I would like to say that the task of spreading literacy and primary education primarily lies with the State Government. Therefore, the question of the State Government referring to the Government of India does not arise; and, So the question of grants for this purpose is also immaterial. However, as I have told this House several times, the Central Government has adopted an adult education programme which will be in force from 2nd October 1978. We have decided that we are to make 10 crores of people literate in five years' time. This is a massive programme. Accordingly, the allotment for West Bengal has gone up. It was decided that 72.89 lakhs within the age group of 15 to 35 in West Bengal should be given facilities for adult education and 50 per cent of the expenses will be borne by the Central Government.

As for spreading primary education in the coming Plan, 43.13 lakhs additional unschooled children of the age group of 14—16 are to be covered under the particular scheme.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I would like to know from the Minister whether he is aware that the West Bengal Government has announced that they will open 1000 primary schools in school-less villages and whether it will help to eradicate illiteracy in West Bengal, and whether he is aware that recently, in West Bengal, the State Education Ministers' meeting was held and opinion was expressed by the Education Ministers'

that Education should be in the State list instead of the Concurrent list and, if so, what is his reaction in this matter?

MR. SPEAKER: The Second part does not arise.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: As regards the first part, I welcome the proposal that 1000 primary schools will be opened in West Bengal. It is entirely a matter for the State Government to implement the proposal.

श्री फिरंगी प्रसाद : किसी भी देश के लिए साक्षरता बड़ी आवश्यक चीज होती है । मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि यह बात राज्यों से सम्बन्धित है यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं उन की अवस्था यह है कि अगर राज्य सरकारें उन की संख्या निश्चित भी कर देती है तो मुख्य रूप से गरीब घरों के लड़के स्कूल में नहीं जाते हैं और जब वे वयस्क हो जाते हैं तब वे वयस्क शिक्षा की ओर भी नहीं जा पाते हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्कूल जाने वाले बच्चों, जो प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित हैं, की जो आयु है, उस को निश्चित कर के राज्य सरकारों को ऐसे परिपत्र जारी करेगी कि उन को निश्चित रूप से शिक्षा दी जाए ? होता क्या है कि प्राथमिक विद्यालयों में नाम तो लिख लिये जाते हैं लेकिन गरीब घरों के बच्चे स्कूलों में बहुत कम जाते हैं और इस बात का मूल्यांकन नहीं होता है कि कितने बच्चे स्कूल नहीं गये जिस का नतीजा यह होता है कि आगे जा कर अशिक्षितों की संख्या बढ़ जाती है । इस दिशा में माननीय मंत्री जी की क्या प्रक्रिया है, यह मैं जानना चाहता हूं । वे इस प्रकार के आदेश जारी करें जोकि देश के लोगों के हित में हों ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित हुआ है । इसलिए अगली योजना में यह तय हुआ है कि सैकड़ों में पचास यानी आधा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करना ही चाहिए और योजना कमीशन ने यह बताया है कि लगभग 450 करोड़ रुपया जो पहली योजना में था, वह बढ़ कर लगभग 900 करोड़ हो जाएगा इस से पता चलता हैं कि अगली योजना में प्रान्तों में प्राथमिकता शिक्षा के विकास और प्रसार के लिए काफी कदम उठाया जाएगा ।

अशिक्षित अन्धे व्यक्तियों की शिक्षा

+

***207. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :**

श्री शंकरसिंहजी वाघेला :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्टूबर, 1978 से देश भर में आरम्भ किए जाने वाले प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्रेल पद्धति के माध्यम से लगभग एक करोड़ अशिक्षित अंधे व्यक्तियों को शिक्षा देने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो अंधे प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए राज्यवार कितने और किन किन स्थानों पर केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ग) अन्धे प्रौढ़ व्यक्तियों को ब्रेल पद्धति से शिक्षा देने और उन्हें तकनीकी शिक्षा देकर आत्म-निर्भर बनाने का कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों या न्यासों को सरकार का क्या सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) समाज कल्याण विभाग दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करना चाहता है, जिसमें एक पत्राचार अनुभाग भी होगा । आशा है यह अशिक्षित दृष्टिहीन व्यक्तियों को ब्रेल के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा देगा तथा स्थानीय संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करके यह दृष्टिहीनों में साक्षरता फैला सकेगा ।

(ग) समाज कल्याण विभाग विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित स्वयंसेवी संगठनों को, जिनमें विकासात्मक गतिविधियों के लिए दृष्टिहीनों से सम्बन्धित संगठन भी शामिल हैं, सहायता देता है ।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : माननीय मंत्री जी ने जो अभी उत्तर दिया है, वह बहुत निराशा-जनक है । देश में एक करोड़ नेत्रहीन व्यक्ति हैं और उनके लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा । केवल एक राष्ट्रीय संस्थान से समूचे देश के नेत्रहीनों को किस तरह से शिक्षा दी जा सकेगी ? हमने अपने प्रश्न के भाग 'ख' में यह पूछा था कि आप प्रत्येक प्रदेश में कितने केन्द्र खोलेंगे, उसका तो उत्तर ही नहीं आया । मंत्री जी जानते हैं कि नेत्रहीनों की शिक्षा विशेष प्रकार की होती है । आप प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चालू करने जा रहे हैं । नेत्रहीनों को तो ब्रेल पद्धति से शिक्षा देनी होती है, के माध्यम से तो वह संभव नहीं है । जब ब्रेल पद्धति के प्रशिक्षित प्राध्यापक हों तभी वह शिक्षा दी जा सकती है । नेत्रहीनों के लिए समाज पर दायित्व है । इसलिए मैं मंत्री जी से जानना